भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2754
16 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: मखाना को बढ़ावा देना

2754. श्री गोपाल जी ठाकुरः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दरभंगा जिला देश में मखाना उत्पादन का प्रमुख केंद्र है जिसमें खेती, अनुसंधान, प्रसंस्करण एवं निर्यात हेतु अपार संभावनाएँ हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का दरभंगा जिले में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार ने इन संभावनाओं को ध्यान में रखकर मखाना बोर्ड स्थापित करने हेतु डीपीआर/व्यवहार्यता प्रतिवेदन, बजट अनुमान या स्थल चयन की कोई प्रक्रिया आरंभ की है;

(घ) वहाँ बोर्ड स्थापित होने से स्थानीय किसानों, निर्यात, प्रसंस्करण इकाइयों एवं रोजगार सृजन को क्या प्रत्यक्ष लाभ होंगे; और

(ङ) क्या सरकार मखाना आधारित उत्पादों हेतु भौगोलिक संकेतक ब्रांडिंग, न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण और अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार हेतु कोई विशेष नीति जारी करने का प्रस्ताव रखती है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): भारत मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो वैश्विक उत्पादन के 80% मखाने का उत्पादन करता है, जिसमें बिहार राज्य, मखाना के राष्ट्रीय उत्पादन में 85% का योगदान देता है। बिहार में दरभंगा जिला मखाना उत्पादन के प्रमुख केंद्रों में से व्यापक रूप से विख्यात है; तथा इस जिले को मखाने के उत्पादन और प्रसंस्करण की अपार क्षमता के लिए भी जाना जाता है। दरभंगा में मखाना के उत्पादन हेतु आईसीएआर-राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। दरभंगा को विशेष रूप से मखाना के लिए 'एक जिला एक उत्पाद' (ओडीओपी) पहल के तहत मान्यता प्रदान की गई है।

(ग) से (ङ): मखाना सेक्टर में ताजे और मूल्यवर्धित उत्पादन दोनों रूपों में अपार क्षमता है, जो संभावित राज्यों में बड़ी संख्या में किसानों और मछुआरों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में सहायक हो सकता है। इस क्षमता का लाभ उठाने हेतु, सरकार द्वारा दिनांक 14.09.2025 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है, जिसका प्रमुख उद्देश्य उत्पादन, प्रोसेसिंग, मूल्यवर्धन, विपणन और निर्यात प्रोत्साहन में सुधार करना है। बोर्ड का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान, उन्नत कृषि तकनीकों, बेहतर उत्पादन और प्रोसेसिंग प्रौद्योगिकी के माध्यम से मखाना के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना है।

भारत सरकार द्वारा पूरे देश में छह वर्षों (अर्थात 2025-26 से 2030-31 तक) के लिए 476.03 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली मखाना के विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना को भी मंजूरी दी गई है। इस योजना के प्रमुख घटकों में मखाना क्षेत्र में आवश्यकता-आधारित अनुसंधान और नवाचार, गुणवत्तापूर्ण बीजों का उत्पादन और वितरण, किसानों और हितधारकों की क्षमता निर्माण और कौशल विकास, बेहतर कटाई पद्धतियां और फसल-उपरांत प्रबंधन, मूल्यवर्धन, ब्रांडिंग और विपणन सहायता, वैश्विक मखाना व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए निर्यात प्रोत्साहन और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण उपाय शामिल हैं।

मखाना के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक अलग से एचएसएन कोड भी निर्मित किया गया है तथा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में ब्रांड प्रचार के लिए मिथिला मखाना को जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है।

******